साप्ताहिक हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 153 | जौनपुर, मंगलवार, 21 जनवरी 2025 | साप्ताहिक दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त समाचार

ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़

ओडिशा, (एजेंसी)। ओडिशा–छत्तीसगढ़ सीमा पर सोमवार सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ मिलकर अंतरराज्यीय सीमा पर कुलारीघाट वन्य क्षेत्र में नक्सल रोधी अभियान शुरू किया। यह जंगल ओडिशा के नौपदा जिले से लगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है। ओडिशा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ''सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी जारी है।

राजद सांसद संजय यादव से मांगी गई 20 करोड़ रुपये की रंगदारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य संजय यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने फोन करके उनसे 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। यादव ने कहा कि फोन करने वाले ने पैसे न देने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस ने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यादव ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया, ''शनिवार को एक व्यक्ति ने मुझे कॉल करके रंगदारी के तौर पर 20 करोड़ रुपये मांगे। उसने मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। मैंने इस संबंध में सचिवालय थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है।'' हालांकि, उन्होंने कॉल करने वाले का नाम बताने से इनकार कर दिया। सचिवालय थाने के प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सांसद की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त बीएड शिक्षकों को हिरासत में लिया

छत्तीसगढ़, (एजेंसी)। पुलिस ने रविवार को रायपुर में कई प्रदर्शनकारी बीएड शिक्षकों को हिरासत में लिया। सिटी एसपी के अनुसार, इन उम्मीदवारों को कानूनी रूप से विरोध करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए सैकड़ों शिक्षकों, जिनमें 300 महिला शिक्षक शामिल हैं, ने शनिवार सुबह 5 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के रायपुर स्थित आधिकारिक आवास पर प्रदर्शन किया। ये शिक्षक राज्य सरकार से नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद उनकी नौकरी खतरे में है, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 2023 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री की आवश्यकता थी और कहा गया था कि इस पद के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) आवश्यक योग्यता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,800 से अधिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश जारी किए,।

संविधान बचाने की बात करने वालों ने ही इसकी मूल भावना बदल दी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही संविधान की मूल भावना को बदल दिया था और उन्हें यहां महाकुंभ में आकर देखना चाहिए कि संविधान का वास्तविक सम्मान क्या होता है और कैसे होता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान की तैयारियों की समीक्षा करने आये मुख्यमंत्री ने पुलिस गैलरी का अवलोकन करने के बाद सेक्टर–चार में त्रिवेणी मार्ग पर स्थित संविधान गैलरी का रुख किया जहां उन्होंने भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तकों, ग्रंथों के पुस्तकालय समेत अन्य प्रमुख

प्रदर्शनी को देखा। मुख्यमंत्री ने कहा, "संविधान हमारे लिए आदर्श है। पूरे देश का संचालन इसी से होता है। कोई भी समाज संविधान और इसकी विधियों के बिना नहीं चलता है। संविधान गैलरी जैसे प्रयासों से नयी पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराने में मदद मिलेगी।" योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में इस गैलरी के जरिए यह प्रयास किया गया है कि मेले में आने वाले लोगों को संविधान के निर्माण, लागू होने और इसके अनुच्छेद के बारे में जानकारी हो। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, "एक पार्टी ने लगातार 55 वर्षों तक निजी हितों के लिए संविधान में संशोधन किए। इन लोगों ने संविधान की मूल भावना को बदल दिया। जो लोग संविधान हाथ में लेकर शपथ लेने का नाटक करते हैं, उनके घर में ना तो संविधान की मूल प्रति होगी और ना ही उन्होंने कभी संविधान पढ़ा होगा।" संविधान गैलरी में लगी प्रदर्शनी में चित्रों और प्रतिकृतियों के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, दस्तावेजों और व्यक्तित्वों के योगदान के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। यहां ऑडियो के माध्यम से संविधान सभा की परिचर्चा को भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

मरीजों को दिल्ली एम्स में मिले बेहतर सुविधाएं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली एम्स में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस चिट्ठी को शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा कि ठिठुरती ठंड में मरीजों और उनके परिजन मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना यह भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं, वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्श्देशभर

से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। पिछले दिनों मैंने देखा कि ठिठुरती ठंड में ये मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। आसपास कूड़े–कचरे का भी ढेर लगा रहता है। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना यह भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं, वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।श उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा, श्श्मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। साथ ही आशा है ।

महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय पर विजय वडेट्टीवार का तंज, बोले पंगु हो गया है ये प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नही

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला की घटना की निंदा की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्रालय को पंगु बताया। कहा ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। विजय वडेट्टीवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि प्रदेश का होम डिपार्मेंट को पैरालिसिस जैसा कुछ हो गया है , यह महाराष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेश का है।'' दिग्गज कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार और भाजपा पर देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र और दिल्ली में सरकार ने अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। भाजपा हिंदू–मुस्लिम झगड़े भड़का रही हैं, वहीं दूसरे देशों के अपराधी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं और अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सरकार ने गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार ने इस मामले की जिम्मेदारी नहीं ली है या इसे गंभीरता से नहीं लिया है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं बची है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक मुंबई पुलिस ने जताया है। उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है जो पुलिस के मुताबिक एक्टर के घर पर चोरी करने पहुंचा था। मुंबई पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि वो बांग्लादेशी है और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया। वह अपने वर्तमान नाम विजय दास का उपयोग कर रहा था। 5–6 महीने पहले मुंबई आया था। बता दें, अभिनेता सैफ अली खान पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में रविवार (19 जनवरी) तड़के ठाणे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। आरोपी को पकड़ने के लिए 35 टीमें लगाई गई थीं। 16 जनवरी को देर रात घर में घुसे हमलावर के हाथों अभिनेता सैफ अली खान घायल हो गए थे।

लखीमपुर हिंसा के गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हुई लखीमपुर हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सख्ती जताई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी पर लगे गवाहों को प्रभावित करने के आरोप पर यूपी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी के एसपी मामले की जांच करके पूरी रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सख्त नाराजगी जाहिर की। वहीं आरोपी आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे ने आरोपों से इन्कार किया। आरोपी के वकील ने कहा कि हर बार जब मामला अदालत के समक्ष आता है, तो शीर्ष अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने

के लिए इस तरह के दावे किए जाते हैं। उनके मुवक्किल को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। जबकि शिकायतकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके पास मामले में महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने आरोप लगाया कि आशीष मिश्रा ने जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। उन्होंने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की। प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत आरोपों की सच्चाई का पता लगा सकती है। इसके बाद पीठ ने भूषण और दवे से कहा कि वे अपनी सामग्री उत्तर प्रदेश सरकार की स्थायी वकील रुचिरा गोयल को सौंप दें ताकि उसे लखीमपुर खीरी के एसपी को सौंप दिया जा सके। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 22 जुलाई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उसे दिल्ली और लखनऊ में न रहने का निर्देश दिया था, ताकि वह गवाहों को प्रभावित न कर सके। इसके बाद 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने की इजाजत दे दी थी। 2021 को हुई हिंसा में गई थी आठ लोगों की जान गौरतलब है कि 3 अक्तूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर दौरे के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान एक कार से कुचलकर चार किसानों की मौत हो गई थी।

बिहार में कांग्रेस तथा वामदलों के साथ हमारा गठबंधन अभी भी : तेजस्वी यादव

औरंगाबाद, (एजेंसी)। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस तथा वामदलों के साथ उनका गठबंधन पहले भी था एवं आज भी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार हम राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी ने सोमवार को औरंगाबाद के जिला अतिथि गृह में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार से आम जनता परेशान तथा आहत है और ऐसी स्थिति में जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश

कुमार कहते हैं कि बिहार में मैंने सब कुछ कर दिया है और अब कुछ करने के लिये बचा नहीं है। उनके पास न अब बिहार के लिए कोई विजन है और नहीं ब्लूप्रिंट। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने राज्य की जनता को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया और अब का दौर आर्थिक न्याय दिलाने का है। यदि हमारी सरकार बनी तो हम आर्थिक न्याय दिलाएंगे। क्या नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा खुला है के सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि अब चुनाव होगा और जनता चुनेगी। तेजस्वी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर होने वाले खर्च को लेकर आरोप लगाते हुये कहा कि गरीब राज्य बिहार में मुख्यमंत्री की यात्रा पर 225.78 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ पटना से आए अधिकारी उन्हें घेरे रहते हैं ।

सीएम योगी से मिला इटली से आया प्रतिनिधिमंडल, सुनाई रामायण की चौपाई

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में रविवार को टली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। महाकुंभ से लौटीं इटली की महिलाओं ने सीएम के सामने रामायण की चौपाई, शिव तांडव, भजनों की प्रस्तुति और महाकुंभ के अनुभव भी साझा किए। इटली में ध्यान एवं योग सेंटर के संस्थापक एवं प्रशिक्षक माही गुरु के नेतृत्व में उनके अनुयायी सीएम से शिष्टाचार भेंट करने आए थे। बता दें, महाकुंभ का आयोजन न सिर्फ भारतीयों, बल्कि विदेशी मेहमानों को भी आकर्षित कर रहा है। इटली से आए इस प्रतिनिधिमंडल ने संगम में स्नान कर भारतीय परंपराओं को समझा। प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ में नागा साधुओं, भजन–कीर्तन और

धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनकर आध्यात्मिक अनुभव भी हासिल किए। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को बताया कि महाकुंभ धार्मिक आयोजन होने के साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रदर्शन है। भारतीय संस्कृति की गहराई और इसकी आध्यात्मिकता ने उन्हें खासा प्रभावित किया है।

भाजपा सरकार से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ : पायलट

जयपुर, (एजेंसी)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के एक साल के कार्यकाल से प्रदेशवासियों को कोई खासा फायदा नहीं हुआ है। पायलट ने सोमवार को सिरोही जाने से पहले उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में भजनलाल सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में केवल योजनाओं को बंद करने, कई जिलों को निरस्त करने और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर पुर्नविचार करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का आने वाले बजट पर कांग्रेस चाहती है कि पूरी तरह से चर्चा हो। सदन चलाने का काम सरकार का है। हम सरकार की जबावदेही तय करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वह आम जनता के लिए काम करे। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभायेगी। हम सदन के पटल पर एवं बाहर अपना पक्ष रखेंगें। हम सभी कार्यकर्ता एवं नेता एक परिवार की तरह से कार्य कर रहे है। पायलट ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही बहुत हावी है। सरकार में बहुत पावर सेक्टर बन गए हैं कि सत्तारूढ दल के जो विधायक है वे भी दर–दर भटक रहे है। सरकार की जवाबदेही तय हो इसके लिए हम विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर पायलट ने कहा कि दिल्ली में जो सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने कई बार मौके दिए हैं। पिछले दस से बारह सालों से केंद्र और राज्य सरकार के वर्चस्व की लड़ाई से दिल्ली के लोग पिस रहे है। इसमें कांग्रेस पार्टी बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार थी तब जो विकास हुआ उसको जनता आज याद कर रही है। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस का परफोरमेंस बेहतर रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हमले पर पायलट ने कहा कि हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए लेकिन जनता जो जवाब मांग रही है,।

राहुल गांधी को मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।

शीर्ष अदालत ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए श्हत्याराश शब्द का प्रयोग किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि नोटिस

जारी किए जा रहे हैं। अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं, जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैसले में शिकायत के संबंध में एक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

कांग्रेस नेता ने रांची की मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया। यहां कोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ आगे की किसी भी कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट ने पाया था कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनता है और उन्हें चार फरवरी 2023 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। बाद में हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि राहुल के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।

संपादकीय

कड़वाहट का कलुष

आज की दुनिया में अपने आसपास का व्यवहार देख कर यही लगता है कि इंसान बहका हुआ है। उसने हर जगह के लिए एक मुखौटा बना रखा है। भोलेपन के पीछे कड़वाहट का समंदर है, लेकिन वह अपनी कलुषित भावना उसको छिपाना चाहता है। ऐसा करते हुए यह भूल जाते है कि हम एक भीड़ हैं। हमारे हजारों मुखौटे हैं। घर में अलग मुखौटा है। उसमें भी माता–पिता के सामने अलग मुखौटा, बच्चों के सामने अलग, पत्नी के सामने अलग, पेशेवर मित्रों के सामने अलग, लंगोटिया मित्रों के सामने अलग, मालिक के सामने अलग और नौकर के सामने अलग। हमारे कितने चेहरे हैं, शायद हमको खुद ही नहीं पता। समाज में जीने के लिए आज यह आवश्यक हो सकता है, लेकिन जीवन जीने में यह मुखौटा पूरी यात्रा के आनंद को कड़वाहट में बदल देता है । जीवन में कड़वाहट का मुख्य कारण अपनी इच्छा और विचार को सर्वोपरि रखना है। इस कारण रिश्तों में दरार, बिखराव और टूटन आता है । आजकल अधिकतर लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता की बहुत कमी है। लोग छोटी–छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। घर से बाहर की बात तो दूर, एक घर के अंदर रहने वाले एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को सम्मान नहीं देते और वाद–विवाद में पड़ जाते हैं । बचपन से जो पिलाया जाता है, वही बच्चे की नस–नस में बस जाता है। बच्चे घर से ही रिश्तों की अवहेलना सीख जाते हैं और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तब कहीं जाकर रिश्ते मधुर होते हैं । हम एक दूसरे का सम्मान करना बंद कर देते हैं, तब रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। कई बार गलतफहमियां भी रिश्ते में कड़वाहट ले आती हैं। कभी–कभी अगर एक पक्ष गलत हो और दूसरा पक्ष सही होते हुए भी उसे बार–बार दबना पड़े तो भी रिश्ते कड़वे हो जाते हैं । कई बार जब हम छोटे और बड़े का यथायोग्य आदर या स्नेह देना बंद कर देते हैं या फिर फालतू का शक करने लगते हैं, तब भी रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है । अगर रिश्तों को बरकरार रखने के लिए हम थोड़ा झुकने के बाद भी रिश्तों को बचा लें, तो यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि होगी। मगर आज झुकना कोई नहीं चाहता है, न ही रुकना । इसलिए हर पड़ाव पर हम खुद का ही मोल लगा बैठते हैं। विनम्रता से हर कोई समझ ही जाता है, लेकिन अगर थोड़ा–बहुत मनमुटाव हो भी, तो भी रिश्ता खत्म नहीं किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि ज्यादातर रिश्ते आजकल दिखावटी रह गए हैं। सहनशीलता और एकता खत्म होती जा रही है। रिश्तों में विश्वास जरूरी है, जहां विश्वास होता है, वहीं प्यार पनपता है। बिना विश्वास प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती । जीवन और रिश्तों के बारे में एक तरह का खाका या मानसिकता देकर जाते हैं । यह मानसिकता हमारे रिश्तों के खुशहाल होने का एक प्रमुख निर्धारण कारक है । स्थायी परिवर्तन तभी आएगा, जब हम इन वफादारियों के बारे में जागरूक होंगे। जीवन में अपने रिश्ते को ठीक करने के ज्ञान को एकीकृत करने से हमें खुद को ठीक करने की शक्ति और अंतर्दृष्टि मिलेगी और निश्चित रूप से हमारे रिश्ते के कौशल में सुधार होगा। इसके लिए जीवन में सच्चे विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास प्राप्त करने का पहला साधन है व्यक्तिगत अनुभव और उससे उभरता भरोसा । यह भरोसा किसी वस्तु या व्यक्ति में भी हो सकता है। विश्वास रूपी गुण को उजागर करने से शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति होती है । ये शक्तियां व्यक्ति को अनुशासित और धैर्यवान बनाती हैं। इन्हीं के बल पर वह इंसान ईश्वरत्व के समीप पहुंचता है। और साथ ही उसके प्रति चिंताएं कम होने लगती हैं और एक पारलौकिक आनंद का अनुभव ज्यादा होने लगता है। संसार में हमारी जो भी यात्रा होती है– काम, धन, पद–प्रतिष्ठा की, उसके केंद्र में आनंद की खोज ही है। लेकिन अगर मार्ग गलत हो तो लक्ष्य कैसे मिल सकता है। उसी तरह ये सारी यात्राएं हालांकि जीवन आनंद की खोज के लिए है, पर यह दौड़ उल्टी दिशा में है। इसलिए आनंद के स्थान पर मिलते हैं असहजता, दुख, उदासी, बेचौनी । मन के निर्मल होने का, उसको निर्मल करने का कोई मार्ग नहीं है। निर्मलता मन के पार जाने की दशा है। शरीर मन और आत्मा– ये तीन परतें हैं हमारे अस्तित्व की । अन्न, जल, कपड़ा और मकान। बड़ी सीमित अवश्यताएं हैं शरीर की । अगर शरीर स्वस्थ हो तो उसकी हम न चिंता करते हैं, ।

हादसों की सड़क

यह शर्मनाक ही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकी व गुणवत्ता की खामियों वाली सड़कों की होती है। यह भयावह है कि वर्ष 2023 में देश में हुई पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब पौने दो लाख लोगों की मौत हुई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अट्ठारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद थे। इन हालात को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। यह विडंबना ही है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर–जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुरूख जताया कि विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में जब भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप में चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं। यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों को तलाशना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनने के बावजूद हादसे बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटनामुक्त बनाने में बाधक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके। साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह जानते हुए कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता। जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं। निस्संदेह, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तब हमें यह सुनने को नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के कुछ ही बाद ही सड़क उखड़ गई या बारिश में घुल गई।

रोजगार सृजन हो और महंगाई पर नियंत्रण

सुरेश

आजादी के बाद, संविधान द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करेंगे, यानी अमीर–गरीब के भेद को मिटाएंगे। हालांकि, संविधान को अंगीकार करने के पौन सदी बाद भी यह भेद जस का तस बना हुआ है। देश में प्रगति तो हो रही है, लेकिन वह चंद धनकुबेरों की संपत्ति बनकर रह गई है। आज भी 10 प्रतिशत लोग देश की 90 प्रतिशत संपत्ति पर हावी हैं, जबकि 90 प्रतिशत लोग 10 प्रतिशत संपत्ति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक देश को पूरी तरह से विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और यह सपना देखा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। वर्तमान सरकार के 11 वर्षों में हमने देश को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना दिया है और अगले वर्षों में तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हालांकि, यह सपना है, पर क्या वास्तविकता में अमीर–गरीब का भेद मिट पाया है? क्या मेहनत करने वालों को रोजगार मिला है? और क्या वजह है कि हर संकट में गरीब और भी अधिक परेशान होता है, जबकि अमीर और भी समृद्ध हो जाते हैं। नए आंकड़े बताते हैं कि एशिया में सबसे अधिक खरबपति भारत में हैं। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना बहुत आकर्षक है, लेकिन इसके लिए जीडीपी विकास दर 8–9 प्रतिशत के बीच रहनी चाहिए। हालांकि, 2024–25 के आर्थिक वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी विकास दर पिछले चार सालों में सबसे कम रही, जो 5.4 प्रतिशत तक गिर गई। इसका कारण महंगाई, शहरी मांग में कमी, महंगी वस्तुएं और घटती उपभोक्ता शक्ति बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त, पूंजी निवेश में कमी और उत्पादकता में अवरोध भी आर्थिक मंदी के कारण बने। वर्ष 2023–24 में भारत ने 8.2 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की थी, जो दर्शाता है कि यदि सही नीतियां अपनाई जाएं, तो आर्थिक वृद्धि संभव है। आगामी बजट में वित्तमंत्री को इस मंदी का ध्यान रखते हुए ऐसे कदम उठाने होंगे जो निवेश को प्रोत्साहित करें, उत्पादकता बढ़ाएं, और रोजगार के अवसर सृजित करें। इसके परिणामस्वरूप मांग में वृद्धि होगी और बाजारों में निरुत्साह की स्थिति को रोका जा सकेगा। कृषि, जो देश का प्रमुख क्षेत्र है और जिसमें 62 प्रतिशत श्रम लगा है, अब उसके जीडीपी योगदान में गिरावट आ रही है। कोविड महामारी के प्रभाव से शहरी औद्योगिक और उत्पादक क्षेत्रों से श्रम बल वापस ग्रामीण इलाकों में लौट आया है, और अब वे शहरों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार, 16 प्रतिशत श्रम बल कृषि से अन्य क्षेत्रों में गया था, लेकिन पिछले दस वर्षों में 19 प्रतिशत श्रम बल खेती में लौट आया है, जबकि खेती की उत्पादकता अन्य क्षेत्रों से कम है। सेवा क्षेत्र और पर्यटन ने जीडीपी में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन रोजगार की संभावना सीमित है। सरकार के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के बावजूद पूंजी निर्माण की कमी के कारण ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई। शहरी उपभोग में गिरावट के साथ ग्रामीण उपभोग में वृद्धि हुई है। सरकार ने सहकारी क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसके लिए इन उद्योगों को गांवों, कस्बों या छोटे शहरों में स्थापित करना आवश्यक है। शहरी महंगाई से गरीब वर्ग का सामना कठिन हो रहा है, जबकि गांवों में खेती का कुटीर उद्योग कुछ सहारा दे सकते हैं। महंगाई का असर गांवों और शहरों दोनों पर है। एक और बड़ी चुनौती यह है कि युवा पीढ़ी को रोजगार की गारंटी नहीं मिल पा रही, खासकर सरकार द्वारा महंगाई नियंत्रण के लिए लागू की गई सख्त साख नीति के कारण। उच्च ब्याज दरों और रैपो रेट में कोई कमी न आने से यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। आगामी माह में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों या रैपो रेट में कटौती की आवश्यकता होगी, ताकि खेती से लेकर निवेश तक को प्रोत्साहन मिल सके और रोजगार सृजन हो सके। वर्तमान में कृषि, होटल और सम्पत्ति क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में विकास दर घट गई है, जैसे निर्माण, खनन, विद्युत, गैस, और व्यापार। इसका कारण निवेश और पूंजी निर्माण की कमी है, जो ब्याज दरों में कटौती से पूरी हो सकती है। हालांकि, ब्याज दरों में कमी महंगाई को बढ़ा सकती है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

आपातकालीन विसंगतियों के ज्वलंत प्रश्न

ज्योति

जहां पिछले सप्ताहांत मुंबई में न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरा शहर इस मुद्दे पर उलझा रहा कि सैफ अली खान को किसने और क्यों चाकू मारा और यह घटना ठीक हिंदी फिल्मी सीन वास्तविक जिंदगी में घटने जैसी रही वहीं पंजाब में अभिनेत्री–निर्देशक कंगना रनौत की इंदिरा गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म 'इमरजेंसी' का 'स्वागत' जिस डर और नफरत की भावना के साथ हो रहा है, वह नए स्तर को छू रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन रोकने वाले माहौल के बीच यह फिल्म बीते शुक्रवार को देशभर में रिलीज हो चुकी है। अब सबको पता है कि एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी शिरोमणि अकाली दल के सदस्य हैं और यह सिख संस्थान भी आरएसएस की भांति अपनी विधिवत स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, इस पर अभी भी काफी हद तक सुखबीर बादल के नेतृत्व वाली पार्टी का नियंत्रण है। आप कह सकते हैं कि एसजीपीसी के एक पदाधिकारी ने तर्कहीन ढंग से जरनैल सिंह भिंडरांवाले को 'महान' ठहराते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि संस्थान कंगना की फिल्म का बहिष्कार क्यों कर रहा है–कदाचित 'सिखों को गलत रूप में पेश किया है' के नाम पर, क्योंकि फिल्म में भिंडरांवाले को श्रीमती गांधी से यह कहते हुए देखा गया है : 'अगर वे एक अलग राज्य देंगी, तो वह उन्हें सिखों की वोटें सुनिश्चित करवाएगा', दूसरे शब्दों में खालिस्तान– जो कि असली दुनिया में संभव नहीं है, जहां तथ्य और कल्पना स्पष्ट रूप से चिन्हित और अलहदा होते हैं और जाहिर है फिल्मों में काल्पनिक घटनाएं डाली होती हैं। लेकिन यह पंजाब है, एक ऐसा राज्य जिसका प्रदर्शन कुछ मापदंडों पर खास बुरा नहीं है– निश्चित रूप से यह खुद के लिए भोजन, कपड़े और शिक्षा का इंतजाम करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है, वर्ना इसके शहर और गांव उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों से भरे न होते– लेकिन यहां अधिकांशतः तोड़ी–मरोड़ी राजनीतिक भावना इतनी हावी रहती है कि वास्तविकता उतनी होती नहीं जितनी प्रतीत होती है। सो यह व्यापक परिदृश्य कंगना–विरोध और उसकी फिल्म इमरजेंसी की मुखालफत के पीछे है। इसके कारक पांच सूत्र कहे जा सकते हैं। सबसे पहला यह कि कंगना एक ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत हैं, जो पूर्व में हुए और अब पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की कटु आलोचना करती आई हैं, पिछले साल जून में सीएसआईएफ की एक महिला कांस्टेबल ने इसको कारण बताते हुए उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया था। दूसरा सूत्र, किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा है। किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल जारी है, जिससे एक और 'मरजीवड़ा जत्था' तैयार हो गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मबलिदानी, 111 किसानों की यह टोली अपनी मांगें मनवाने के लिए 'करो या मरो' की नीति के साथ, हरियाणा से होकर दिल्ली पहुंचने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि इस बार किसान पंजाब की नब्ज पर हाथ रखने में उतने सफल नहीं रहे, जैसा कि चार साल पहले कर पाए थे दृ दिल्ली की तो बात ही छोड़िए दृ तब प्रधानमंत्री मोदी को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था, यह एकमात्र ऐसा मौका था जिसने उन्हें अपने कहे से पीछे हटने को मजबूर किया था। डल्लेवाल का तथाकथित 'सत्याग्रह' आज विफल हो रहा है। सवाल मंशा को लेकर है। तीसरा, किसी को उम्मीद होगी कि किसानों के विरोध से लोगों को होने वाली परेशानी के फलस्वरूप कम से कम कुछ तो जमीन भाजपा की ओर खिसकेगी। इसके साथ ही, भाजपा को उम्मीद जगी है कि सिख किसानों और पंजाब के मध्य वर्ग की शहरों में बसने की ललकदृ जिसके तहत वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर की कूड़े–कर्कट से भरी सड़कों वाले माहौल में रहने की बजाय कनाडा में बसना कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैंदृ इससे लोगों का झुकाव मोदी की और अधिक बनेगा। चौथा, यहीं पर भाजपा गच्चा खा गई। भले ही किसानों के विरोध के ढंग में सब कुछ गलत हो लेकिन फिर भी भाजपा को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वास्तव में, स्थिति इसके ठीक उलट है। पंजाब की राजनीति कई दिशाओं में बिखरती लग रही है दृ आज तीन अकाली दल हैं, जिनमें खडूर साहिब से नए बने सांसद और कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल की 'वारिस पंजाब दे' से लेकर सिमरनजीत सिंह मान के अकाली दल (अमृतसर) के अलावा बादल की पुरानी पार्टी शामिल है, जो कि खुद आंतरिक रूप से विभाजित है, भले ही इसके असंतुष्ट राजनेता अलग–अलग दलों में जा रहे हैं, ज्यादातर 'आप' में दृ लेकिन भाजपा में शामिल होने को अभी भी वर्जित माना जाता है। पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जैसे भाजपा उम्मीदवारों की या तो जमानत जब्त हो गई या वे हालिया उपचुनावों में अंतिम स्थान पर रहे। पांचवां सूत्र, यह सवाल कि क्यों पंजाब खुद को एक 'अलहदा ध्रुव' मानता है, जो ठीक उसका उलट करे जो करना दिल्ली को पसंद हो –'अकाल तख्त' बनाम 'दिल्ली तख्त'? इसका उत्तर भी उतना ही सरल है। पंजाबियों का मानना है कि दिल्ली को इनकी परवाह नहीं है, अगर होती तो वह राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी अनेकानेक समस्याओं को ठीक करने में मदद करती दृ जिसमें धान और अब गेहूं की खरीद से लेकर ड्रोन एवं अन्य तरीकों से आते नशे की समस्या, कानून व्यवस्था की गिरती हालत और इसके अलावा गैंगस्टर–वाद और अन्य अनगिनत समस्याएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए एसजीपीसी –और नाखुश पंजाबियों का एक बड़ा वर्ग– 'इमरजेंसी' की स्क्रीनिंग के खिलाफ है, वह यह है कि उन्हें डर है कि फिल्म पंजाब को देश और दुनिया के बाकी हिस्सों के सामने 'बुरे अक्स' में पेश करती है– जिसका मतलब है, आज वाले 'खालिस्तानी' भी भिंडरांवाले से कम बुरे नहीं हैं। उनकी सोच है कि इस फिल्म से बाकी भारत यह मान बैठेगा कि पंजाब आज उस भयानक दौर में फिर से वापस फिसल सकता है क्योंकि इसने एनएसए और यूएपीए कानून के तहत जेल में बंद एक कट्टरपंथी सिख के अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को सांसद चुना है दृ आशंकित करने के लिए इतना काफी है। विद्रोही होने तक तो बात ठीक है, लेकिन कट्टरपंथ? सच तो यह है कि बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि कैसे उन भयानक वर्षों के दौरान पंजाब ने अपना नुकसान किया था (कोई आश्चर्य नहीं, आज कनाडा बैठों के इशारे पर) और अब वह दुःस्वप्न फिर से वापसी कर सकता है, तमाम उन रंगों में, पंजाब को जतलाने कि इसके साथ गलत क्या है। लोगों को निराश करने के लिए यह काफी है। अमृतसर से राजनीति शास्त्र के दो विशेषज्ञ जगरूप सिंह सेखों और परमजीत सिंह जज, जिन्होंने पिछले इन कई दशकों में पंजाब का पराभव देखा, वे मौजूदा व्याप्त दिशाहीनता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि संस्थानों में विश्वास की कमी, कृषि संकट, अस्पष्ट भावी रोडमैप जैसे कारक हैं। सेखों ने कहा 'लोगों ने दिल छोड़ दिया है'। हालांकि, उनसे अधिक आशावादी परमजीत जोर देकर कहते हैं कि जल्द ही या किसी दिन यह ज्वार उतर जाएगा, खासकर जब राजनीति को शून्यता नापसंद है। सो, प्रिय पाठकों, आप जब 'इमरजेंसी' देखने के लिए कुलबुलाएं, तो भी विचार करें कि अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा द्वारा पिछले सप्ताह की शुरुआत में मुक्तसर में माघी मेले में एक खुले मंच पर एक साथ आकर अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की शुरुआत करने के पीछे क्या विशेष है। सच तो यह है कि यह सिर्फ पंजाब ही है जहां एक राजनीतिक पार्टी का मुखिया एक ऐसा सांसद हो सकता है जो एनएसए और यूएपीए के तहत जेल में बंद है, वो बात अलग है कि सांसद के रूप में शपथ उसने संविधान की ली है। यह सिर्फ पंजाब ही है, जहां कट्टरपंथियों का पक्ष लेने वाली पार्टी को चुनाव आयोग से मंजूरी मिली है। सिर्फ पंजाब में ही जहां अतीत और वर्तमान इतने गड–मड हैं कि कभी–कभी एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब आप कोई फिल्म देख रहे हों।

एमएसपी और आठवां वेतन आयोग

पिछले 55 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आखिरकार चिकित्सा सहायता लेने के लिए राजी हो गए हैं। श्री डल्लेवाल ने यह मंजूरी तब दी जब केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि आगामी 14 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों से वह बातचीत करेगी। हालांकि जगजीत सिंह डल्लेवाल अब भी इस बात पर अडिग हैं कि वह मांगें पूरी होने तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। पिछले 11 महीनों से आंदोलन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर–राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों से केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। बैठक के ऐलान के बाद किसान नेताओं ने डल्लेवाल से अनुरोध किया कि वे चिकित्सा सहायता लें ताकि वे इस प्रस्तावित बैठक में हिस्सा ले सकें। श्री डल्लेवाल का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है और इस पर अदालत भी चिंता जतला चुकी है, लेकिन सरकार इस बारे में सही में कितनी फिक्रमंद है, यह विचारणीय है। पिछले साल 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा पर आंदोलनकारी किसान डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उन्हें अपनी फसलों के लिए कानूनी एमएसपी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली तक मार्च करने की अनुमति नहीं दी थी। पिछले साल 8, 12, 15 और 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच चार दौर की बैठकें हुई थीं, जो बेनतीजा रही थी। अब एक लंबे अंतराल के बाद फिर से किसानों के साथ बैठक प्रस्तावित हुई है, जिसका क्या नतीजा निकलेगा इस बारे में कुछ भी कहना कठिन है। पिछले अनुभव तो यही बताते हैं कि सरकार हद दर्जे की हठधर्मिता दिखाती है। वह हर हाल में किसानों को मजबूर और लाचार बनाकर झुकाना चाहती है। इससे पहले जब 2020–21 में किसानों ने ऐसा ही लंबा आंदोलन किया था, तो आखिर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहकर तीनों कृषि कानून वापस लिए थे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, जो मैं समझा नहीं पाया। यानी यहां भी सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी, केवल यह स्वीकार किया था कि किसान कृषि कानूनों की उपयोगिता नहीं समझ सके। किसान तब कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनी फसलों के लिए मांग रहे थे, अब भी उनकी मांग वही है। लेकिन सरकार के तर्क भी वही हैं कि इससे सरकारी कोष पर भार बढ़ेगा। आश्चर्य यह है कि जब सरकार आठवां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देती है, तब उसे इस वित्तीय भार की चिंता नहीं होती। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केन्द्रीय कर्मियों को लाभ होगा, साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अकेले दिल्ली में ही लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में अगले महीने की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा उम्मीद लगा कर बैठी है कि उसका 26 सालों का वनवास खत्म होगा और उसे दिल्ली की सत्ता भी मिलेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तगड़ी तैयारियों के आगे भाजपा के लिए सत्ता हासिल करना कठिन चुनौती है। भाजपा की मुश्किल आसान करने के लिए ही शायद मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया, ताकि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी आबादी के वोट उसके लिए सुनिश्चित हो जाएं। जानकारी के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम आधार वेतन को बढ़ाकर 34,650 रुपये किया जा सकता है, जो कि सातवें वेतन आयोग में 17,990 रुपये है। वहीं, पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये किया जा सकता है। हालांकि, ये सिर्फ संभावना है, अगले साल 2026 में जब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तब असल आंकड़े सामने आएंगे। पाठकों को बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं, जो 2026 में समाप्त हो रही हैं। सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016–17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। आठवें वेतन आयोग से सरकार पर करीब दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। सरकारी कर्मचारियों ने वेतन या पेंशन बढ़ाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, सड़कों पर दिन–रात नहीं बैठे, अपनी रोजी–रोटी दांव पर नहीं लगाई, फिर भी सरकार ने चलन के अनुसार हर दस साल में वेतन आयोग गठित करने की परिपाटी का पालन किया और वेतन बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। अच्छी बात है कि जिन लोगों की वजह से सरकार का कामकाज सुचारू चलता है और देश में व्यवस्था बने रहती है, उनके हक का ध्यान सरकार ने रखा। लेकिन क्या सरकार का यही रवैया किसानों के प्रति भी नहीं होना चाहिए। किसान भी तो दिन–रात, सभी मौसमों में काम करके देश के लिए अनाज उगाते हैं। और वे अपनी मेहनत के बदले अनाप–शनाप मांग भी नहीं करते,

केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहते हैं ताकि उनकी लागत वसूल हो सके और नयी फसल उगाने के लिए वे खाद–पानी–बीज की अच्छी व्यवस्था कर सकें। यह कोई बेजा मांग नहीं है, जिसे सरकार लगातार अनसुना कर रही है। 2021 के आंदोलन के बाद एमएसपी के लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी। उस समिति की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। अब फिर से पिछले 11 महीनों से एक नया आंदोलन शुरु हुआ है और उसकी तरफ भी सरकार का रवैया बेरुखा ही रहा है। यह रवैया चुनावों के वक्त जरूर उदार हो जाता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में धान की खरीद 2300 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी की बजाय 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर करना मुमकिन हो गया था, क्योंकि वहां करोड़ किसानों को सालाना छह हजार रुपये की सहायता देती है। लेकिन खैरात की तरह साल के छह हजार रूपए देने की जगह अगर एमएसपी की मांग सरकार पूरी करे तो किसानों का आत्मसम्मान बचेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, देश में कृषि का विकास होगा और इन सबसे आखिर में देश की आर्थिक व्यवस्था को ही मजबूती मिलेगी। चुनावी गुणा–भाग करने की माहिर सरकार इतना सीधा सा हिसाब क्यों नहीं लगा पा रही है।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है : जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में प्रदेश का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। यहां की कला परंपरा में गायन, वादन, नृत्य और लोकनाट्य की विभिन्न शैलियों के प्रमुख गुरुओं और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन कलागुरुओं ने अपनी साधना से न केवल कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बल्कि देश का मान भी बढ़ाया है। उक्त बातें जिलाधिकारी डॉ दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सामुदायिक भवन में संस्कृति उत्सव 2024–25 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। साथ ही कहा जौनपुर में कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सामुदायिक भवन में संस्कृति उत्सव 2024–25 का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से हर वर्ष आयोजित होने वाले इस उत्सव में गांव, ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तर के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस आयोजन की खास बात यह है कि चयनित प्रतिभाओं को मंडल स्तर और प्रदेश स्तर पर अपनी कला दिखाने का अवसर भी मिलेगा। कार्यक्रम में सभी कलाकारों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और अपना ऑडिशन देने की अपील की गई है, ताकि वे आगे चलकर अपने और जनपद का नाम रोशन कर सकें।

भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य कर रही है - अर्चना मिश्रा

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रबुद्ध वर्ग जिला संगोष्ठी में मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा ने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और सिद्धांतों का चीरहरण कांग्रेस शासनकाल मे हुआ। भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब के समानता के विचार पर भाजपा ने काम करते हुए आर्थिक रूप से देश के सभी नागरिकों का जनधन योजना के जरिए शून्य बैलेंस के साथ बैंक में खाता खुलवाकर सबको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। अमीर गरीब के बीच की खाई को पटने का काम भाजपा ने किया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य कर रही है। बाबा साहेब एक देश में दो संविधान , दो निशान के खिलाफ थे, पर नेहरू गांधी परिवार की तुष्टीकरण की राजनीति ने देश के भीतर खाई खोदने का काम किया। उसी धारा 370 को हटा कर देश को एक सूत्र में पिरोकर बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा किया गया। बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान भी 1990 में जब भाजपा समर्थित सरकार बनी तब दिया गया। नेहरू गांधी परिवार ने देश को अपनी जागीर समझ रखा था। देश में कई दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने लगातार बाबा साहब को अपमानित किया। संविधान का लगातार दुरुप्रयोग करते हुए 85 से भी ज्यादा बार संविधान को संशोधित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का कार्य किया। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित अनुसूचित वर्ग के बुद्धिजीवियों से कहा कि बाबा साहेब देश की धरोहर है। बाबा साहेब को सिर्फ वोट की राजनीति तक न समेटे। अर्चना मिश्रा ने संगोष्ठी में बौद्धिक वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा बाबा साहेब अंबडेकर के विरोध में रही है और अचानक कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है। पूर्व पीएम नेहरू द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति किए गए अपमान के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं को पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देता है, तो सदन में उसे बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के इस्तीफे के बाद सदन में कांग्रेस ने बोलने तक नहीं दिया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने त्याग पत्र में पंडित नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। बाबा साहेब ने लिखा था कि वित्त और उद्योग क्षेत्र में पढ़ा–लिखा होने के बावजूद भी पंडित नेहरू ने मुझे उससे जुड़ा एक भी विभाग नहीं दिया और एक भी संसदीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया। बाबा साहेब ने लिखा था मुझे कानून मंत्रालय दिया तो गया, मगर ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल के कार्य को पूरा नहीं करने दिया। कहा कि बाबा साहेब ने अपने त्याग पत्र में लिखा था कि कांग्रेस ने केवल मुसलमानों की चिंता की, लेकिन एससी और एसटी को उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया। कांग्रेस का सारा ध्यान मुस्लिम समुदाय के प्रति समर्पित रहता है। वहीं जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने संगोष्ठी में विपक्ष की नियत पर सवाल उठते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस को सत्ता मिली, उन्होंने अनुसूचित जातियों पर अत्याचार किए। कांग्रेस की नीतियां हमेशा देश को कमजोर करने वाली रही हैं। उन्होंने जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर समाज में फूट डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसान, महिला, युवा और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि देश अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि विकास का केंद्र बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे बाबा साहब के घर को स्मारक में तब्दील करना और उनकी शिक्षाओं को जन–जन तक पहुंचाना। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती है, जबकि भाजपा देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। एलोरा तीर्थ के बौद्ध धर्म अनुयाई डॉक्टर ने बताया कि भारत का संविधान बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पंचशील का मतलब है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। जो भी नागरिक इन सिद्धांतों को अक्षरशः पालन करता है वह सही मायने में संविधान का सम्मान करता रहा है। पंचशील के पालन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति तो होती है, इससे भारत के आत्म बल को शक्ति मिलती है। संगोष्ठी को युवा मोर्चा अध्यक्ष आकाश सिंह, महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका गुप्ता, अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष महिपाल गौतम ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री ओम वर्मा ने किया। संगोष्ठी में उपस्थित रहे बौद्ध धर्म अनुयाई डॉक्टर बुद्धि प्रिय, धम्मपाल, जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित, जिला महामंत्री अनुराग मिश्र, सत्येंद्र राजपूत, मंत्री मीना वर्मा, नीतू चंद्रा, अविनाश पांडेय, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मीना कुमारी, महेंद्र वाल्मीकि, पूर्व अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष सूर्यसेन पासी, मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक, प्रचार मंत्री संदीप अवस्थी, सह मीडिया प्रभारी परेश लोहिया, सत्यम शुक्ल, आईटी संयोजक सौरभ सिंह, नगर अध्यक्ष मुदित बाजपेई, पूर्व नगर अध्यक्ष अजीत उपाध्याय, निधि सिंह, सुहाना जैन, शोभना सिंह एवं गणमान्य व्यक्ति रहे।

राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद भारत कायस्थों के उत्थान के लिए कार्य करती : गिरिजेश श्रीवास्तव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद भारत जौनपुर के जिलाध्यक्ष गिरिजेश श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद भारत एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है और पूरे देश प्रदेश में टीम राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई मयंक श्रीवास्तव जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ एन के सिन्हा जी राष्ट्रीय सचिव राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया एडवोकेट के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही हैं और कायस्थ समाज के लोग तेजी से जुड़ रहे है । राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद भारत कायस्थों के उत्थान के लिए कार्य करती हैं अभी कानपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ई मयंक श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा सैकड़ों नौजवानों को रोजगार नौकरी एवं महिलाओं को आत्म निभर बनाने हेतु सिलाई मशीन वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष गिरिजेश श्रीवास्तव ने कहा कि सामाजिक संगठन के हित के लिए सदैव राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद जौनपुर कार्य करता रहेगा और जल्दी ही जौनपुर में एक समर्पित लोगो के टीम का गठन किया जायेगा और राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद जौनपुर टीम का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा जिसमें संरक्षक आर के सिन्हा बाबूजी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ई मयंक श्रीवास्तव जी, श्री चित्रगुप्त पूजन महासमिति के लोगो एवं सभी कायस्थ संगठनो को आमंत्रित किया जाएगा।

कोई भी क्षेत्रीय दल या राजनीतिक गठबंधन अब बीजेपी के सामने अब नहीं टिक पाएगा : स्वामी चिन्मयानंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

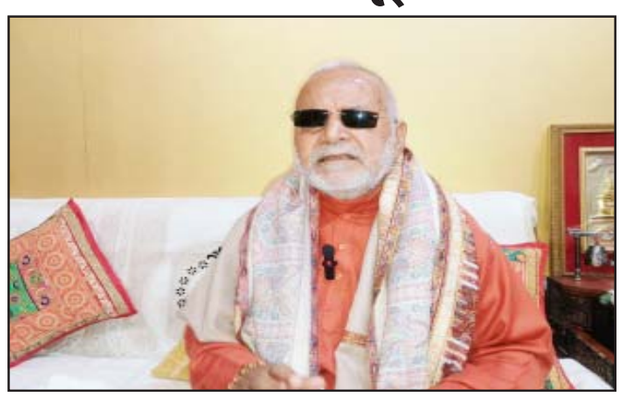

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । प्रयागराज महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर हुए विशाल स्नान के बाद पूर्व गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की भूरि–भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि लगभग डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया, जो इस आयोजन की अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने आस्था के इस महापर्व को इतना महत्व दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों से कुंभ की व्यवस्थाएं चाक–चौबंद हैं। उन्होंने बताया कि प्रयाग का महाकुंभ विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और दुनियाभर से लोग यहां स्नान करने और इस दिव्य आयोजन को देखने आ रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दुनिया के किसी भी धर्म या मजहब के तीर्थस्थल पर इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबे समय तक लोगों का जमावड़ा नहीं देखा जाता, जितना प्रयाग में होता है। उन्होंने कहा कि कुंभ ऐसा पर्व है जहां भारत की विविधता, जातीयता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता की सभी दीवारें टूट जाती हैं। यह आयोजन राष्ट्र की सनातन संस्कृति का प्रतीक बन गया है, जो सामाजिक एकता का संदेश देता है। उक्त बातें मंगलवार को जौनपुर में देश की उपासना ब्यूरो से बात करते हुए कही। प्रयागराज महाकुंभ में स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि इस आयोजन ने भारत की एकता और अखंडता को एक बार फिर साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोग देश में सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सांप्रदायिक दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कुंभ ने इन सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। स्वामी जी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा श्बांटोगे तो काटोगेश सार्थक साबित हुआ है। लोगों ने दिखा दिया है कि वे बंटने नहीं, जुड़ने के लिए तैयार हैं। महाकुंभ के पहले 10 दिनों में ही इसका वैश्विक प्रभाव देखने को मिला, जहां आईफोन की मालकिन सहित विश्व के बड़े कॉरपोरेट घरानों के लोगों ने भी संगम में स्नान किया। उन्होंने सरकार द्वारा गंगा के घाटों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की भी सराहना की। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद यह दूसरा ऐसा अवसर है, जिसने देश को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एकजुट किया है। जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने देश को सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी, वहीं महाकुंभ में लोग इस स्वतंत्रता का उल्लास के साथ आनंद ले रहे हैं।

प्रयागराज कुंभ मेले में स्वामी चिन्मयानंद ने सनातन धर्म की महिमा का बखान करते हुए कहा कि यह कुंभ स्वाधीनता के सही अर्थ को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर्व को सांस्कृतिक या ऐतिहासिक की बजाय आध्यात्मिक पर्व कहना अधिक उचित होगा। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरातन चीजें इतिहास का हिस्सा हो सकती हैं और उन्हें खतरा हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म हमेशा आध्यात्मिक रहा है। जो आध्यात्मिक है वह अविनाशी है, जबकि ऐतिहासिक चीजें विनाशी होती हैं। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित करना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का सकारात्मक संकेत है। बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने शेख हसीना के नेतृत्व में देश की प्रगति की बात कही।

चिन्मयानंद ने भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीडीए गठबंधन अब नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि इस कुंभ में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग श्हर हर गंगेश का जाप कर रहे हैं। उनका मानना है कि कोई भी क्षेत्रीय दल या राजनीतिक गठबंधन अब बीजेपी के सामने अब नहीं टिक पाएगा। आप पार्टी और कांग्रेस आपस में दिल्ली में लड़े लेकिन विजय सिर्फ बीजेपी को मिलेगी बीजेपी के साथ पूरा देश खड़ा हैअब न समाजवाद न क्षेत्रवाद न जातिवाद ना संप्रदायवाद अब सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा।

महाकुम्भ में देवदूत के रुप में दुर्गेश,श्याम व अमित की टीम

प्रयागराज। प्रयागराज में जहाँ महाकुम्भ अपनी भव्यता को ग्रहण कर रहा है वहीं जनपद प्रयागराज में ही पदस्थ समीक्षा अधिकारी शांडिल्य दुर्गेश,कुमार श्याम,अमित रघुवंशी,सुनील यादव,शिक्षक अंकुर पाण्डेय व श्याम सिंह की नर सेवा–नारायण सेवा की टीम इस कड़ाके की ठण्ड में महाकुम्भ क्षेत्र में कम्बल सेवा हेतु विगत 01 जनवरी से देवदूत के रूप में कार्य कर रही है।यह टीम सेवा व विनम्रता के भाव के साथ प्रयागराज व महाकुम्भ क्षेत्र में प्रतिदिन रात में सड़क,फुटपाथ,पार्क के किनारे ठण्ड से ठिठुर रहे दीन–हीन–असहायों को खोजकर कम्बल के माध्यम से सेवा करके उन्हें ठण्ड से बचाती है तथा उन्हें फल,बिस्किट,ब्रेड आदि देती है,साथ ही साथ उन्हें नशाखोरी से बचने के लिये जागरूक भी करती है।टीम के सदस्य बताते हैं कि कभी–कभी ऐसा भी होता है कि कम्बल सेवा के समय मानसिक अवसाद से ग्रसित कुछ व्यक्ति उग्र भी हो जाते है,कम्बल फेंक देते हैं फिर भी टीम पूर्ण धैर्य व समर्पण के साथ उनकी सेवा करती है।ज्ञातव्य हो कि शांडिल्य दुर्गेश अपने सामाजिक व रचनात्मक कार्यों के लिये प्रख्यात हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ कुमार श्याम,अमित सिंह व सुनील यादव देते हैं,जिससे कोई भी सामाजिक कार्य सफलता की तरफ अग्रसर हो जाता है।इस नेक कार्य में श्री शांडिल्य के मित्र,प्रशासनिक अधिकारीगण सहित टीम से जुड़े सभी लोग तन–मन–धन से सहयोग करते हैं।यह कम्बल सेवा विगत नौ वर्षों से चल रही है व प्रतिवर्ष पंद्रह दिन तक चलती है।प्रयागराज में नर सेवा–नारायण सेवा टीम के इस अनुकरणीय कार्य की सभी साधु–संतजन प्रशंसा कर रहें हैं व इसे मानवता की अनूठी मिशाल बताते हुए साधुवाद दे रहें हैं।

अवादा ग्रुप ले जाएगा हजारों लोगों को कुंभ यात्रा पर

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। अवादा ग्रुप ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए सोनभद्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के लगभग 1000 लोगों को प्रयागराज कुंभ मेले में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। यह यात्रा 25 जनवरी से शुरू होगी और यात्रा के दौरान रहने, खाने–पीने, मेला घूमने और दर्शन की सभी व्यवस्थाएं फाउंडेशन द्वारा की जाएंगी। सोनभद्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई गांवों के ग्राम प्रधान और नागरिकों में इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में शामिल होने की उनकी इच्छा कई वर्षों से थी और इस बार का प्रयाग कुंभ तो और भी विशेष है। एक ग्राम प्रधान ने कहा, ष्तीर्थ यात्रा तो आत्मीय स्वजन ही करवाते हैं और अवादा फाउंडेशन तो हमारे स्वजन से भी बढ़कर है। अवादा ग्रुप की चेयरमैन विनीत मित्तल ने कहा, ष्हमारे लिए यह एक विशेष अवसर है कि हम सोनभद्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के निवासियों को इस पवित्र यात्रा पर ले जा रहे हैं। सोनभद्र से आदिवासी समुदाय के लोग भी इस महाकुंभ का लाभ लेने के लिए जा साथ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी को कुंभ के पावन जल में डुबकी लगाने और भगवान का आशीर्वाद लेने का मौका मिले। अवादा ग्रुप की इस योजना से सोनभद्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह यात्रा न केवल उनके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव होगी बल्कि उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों से मिलने का भी अवसर मिलेगा।

महाकुंभ में पुण्य के भागी बनेंगे गौतम अदाणी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। दुनिया के जाने माने उद्योगति गौतम अदाणी आज मंगलवार को महाकुंभ में पुण्य के भागी बनेंगे। वह महाकुंभ 2025 के मौके पर प्रयागराज की यात्रा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह इस्कॉन पंडाल में भंडारा सेवा करेंगे। इसके साथ–साथ त्रिवेणी में पूजा–अर्चना के बाद अतिप्रसिद्ध बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। अदाणी समूह इस वर्ष इस्कॉन और गीता प्रेस के साथ मिलकर महाकुंभ आने वाले श्रृद्धालुओं की सेवा में लगा हुआ है। इस्कॉन के साथ मिलकर अदाणी समूह प्रतिदिन 1 लाख श्रृद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस के साथ मिलजुल कर अदाणी समूह 1 करोड़ आरती संग्रह का वितरण कर रहा है।

चौकियां माई का शृंगार महोत्सव, की तैयारी शुरू

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। देश की प्रसिद्ध मंदिरों में एक सिद्धपीठ माता शीतला मंदिर चौकियां धाम जी का शृंगार महोत्सव दिनांक 23,24,25 जनवरी को होगा जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है पूरे मंदिर परिसर को सुन्दर भव्य रूप से सजाया जा रहा है कोलकाता के कारीगरों द्वारा माता शीतला शृंगार सजावट फूलों द्वारा किया जा रहा है आयोजन समिति के लोगो ने जिलाधिकारी जौनपुर डॉ दिनेश चन्द जी से मिलकर आमंत्रित किया। जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया। चौकियां धाम का नीरीक्षण सिटी मजिस्ट्रेट, सी ओ सिटी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अन्य अधिकारी ने निरीक्षण किया और उचित आदेश दिया। शृंगार में लाखों भक्त दर्शन करने आते है।प्रातः 5 बजे मंदिर खुलने से रात्रि 9 बजे तक दर्शन पूजन श्रद्धालु कर सकेंगें। समस्त कार्यक्रम का आयोजन श्री शीतला जी मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा । चौकियां मंदिर के मंहत विवेकानंद विवेक गुरुजी ने बताया कि शृंगार महोत्सव का सारा खर्च श्री शीतला जी मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा किया जाता हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष विकास पड़ा, प्रबंधक अजय पंडा, पुजारी लल्लन पंडा, माता के भक्त राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया एडवोकेट, महंत विवेकानंद पंडा मंदिर अध्यक्ष विकास पंडा प्रबंधक अजय पंडा, पुजारी लल्लन पंडा व चंद्रदेव पंडा, दिनेश पंडा ,जय नारायण पंडा , भरत श्याम पंडा, प्रवीण पंडा एवं ट्रस्ट के लोग तैयारी पूर्ण करने में लगे हुए है।

संविधान की उद्देशिका का उच्चारण कर सभी को अनुसरण कराया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखीमपुर। गोला गोकर्णनाथ में प्रांतीय आह्वान और भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के निर्देश पर गौशाला सभागार में संविधान गौरव समारोह के तहत डाक्टर अम्बेडकर सम्मान सभा में बतौर मुख्य अतिथि विजय कुमार शुक्ला अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गोला गोकरणनाथ ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ हिन्दू दलितों को देने का कार्य किया। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने संविधान को खतरा बता कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम किया वहीं भारतीय संविधान को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर आंखों पर रखने के साथ बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ बना का कर सम्मान किया। सभा के संयोजक लखीमपुर से आए चन्दन लाल वाल्मीकि ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बराबरी और समानता का अधिकार संविधान में लिखा। जबकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में गैर जरूरी संशोधन कर कांग्रेस ने संविधान और बाबा साहेब को प्रारंभ की लोकसभा में कांग्रेस ने हरवाने का काम कर अपमानित करने का काम किया। चंदन लाल वाल्मीकि ने अनुसूचित के वरिष्ठ समाजसेवी हरीश भारती, सभासद धर्मेंद्र कुमार, महंत मनोज वाल्मीकि, रामाधार सहित मुख्य अतिथि विजय शुक्ला रिंकू जी को संविधान का प्रतीक चिन्ह जगमोहन लाल वाल्मीकि तथा रतन लाल ने देकर सम्मानित किया। सभा के सहसंयोजक हरीश भारती जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा ने कहा कि संविधान की रक्षा और सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया।कांग्रेस ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर सिफ तमाशा करने का काम किया। संयोजक चंदन लाल वाल्मीकि ने सभा के प्रारंभ में बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि और सभा के अंत तक संविधान की उद्देशिका का उच्चारण कर सभी को अनुसरण कराया।

मराठी समाज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री पांडूरंग राऊत, मराठी समाज शिवज्योत यात्रा के प्रभारी नियुक्त

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। मराठी समाज उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग हुई, जिसमे 19 फरवरी 2025 को होनेवाले छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव कार्यक्रम के संदर्भ मे मीटिंग हुई, जिसमे मराठी समाज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री श्री पांडूरंग राऊत जी को मराठी समाज शिवज्योत यात्रा का प्रभारी नियुक्त कियास मराठी समाज शिवज्योत यात्रा का प्रारंभ 2018 के शिवजयंती उत्सव कार्यक्रम के दरम्यान शिवनेरी कीले से हूई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मस्थान है। छत्रपती शिवाजी महाराज की यह यात्रा प्रथम वर्ष मराठी समाज् उत्त्र प्रदेश ने 2018 मे 105 मोटरसाइकल सवार द्वारा शिवनेरी(पुणे) से लखनऊ शिवज्योत यात्रा 1600 किलोमीटर अंतर बाईक से पार करते हुवे आयी व 19 फरवरी 2018 को भारत देश की सबसे बडी शिवजयंती राष्ट्रीय उत्सव के रूप लखनऊ ,उत्तर प्रदेश मे मनाया जाने लगा यही से शिवजयंती की प्रथा लखनऊ मे आज भी मानाई जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी यह त्यौहार हर राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसके लिए अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा तक यह शिवज्योत बाइक यात्रा ले जा चुके है व शिवजयंती उत्सव मनाया जाने लगा है ।

सात वर्षों से राजकीय महिला महाविद्यालय बनकर तैयार, छात्राओं को पढ़ाई शुरू होने का इंतजार

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के सीतापुर में राजकीय महिला महाविद्यालय, नैमिषारण्य में उच्च शिक्षा ग्रहण करना छात्राओं के लिए सपना बनकर रह गया है। करीब सात साल से छात्राएं महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू होने की राह देख रही हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी से उन्हें करीब 10 किलोमीटर दूर चलकर प्राइवेट महाविद्यालयों में दाखिला लेना पड़ रहा है। इससे उन्हें काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। नैमिषारण्य जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर कोई राजकीय महिला महाविद्यालय न होने पर शासन ने वर्ष 2016 में ठाकुरनगर गांव में इसके निर्माण की मंजूरी दी थी।इसके बाद 8 करोड़ 43 लाख 74 हजार रुपये की लागत से वर्ष 2017 में तीन मंजिला भवन बनकर तैयार हुआ था। इससे छात्राओं को उम्मीद जगी थी कि वह दूरदराज न जाकर सीधे राजकीय महाविद्यालय में दाखिल लेंगी, लेकिन सात साल से यह उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। हर साल जुलाई में महाविद्यालय शुरू होने की कवायद होती है, लेकिन यह अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। इससे छात्राओं को करीब 10 किमी दूर निजी महाविद्यालयों में पढ़ने जाना पड़ता है।

सहमति न मिलने से अटका संचालन

एक महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि पहले इस राजकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के माध्यम से चलाया जाना था। इसमें विश्वविद्यालय स्तर से स्टाफ की तैनाती व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी थीं, लेकिन इस नीति पर शासन स्तर से कुछ सहमति नहीं बन सकी। इससे संचालन अटका हुआ है।

सोशल मीडिया पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा

महाविद्यालय के संचालन को लेकर सोशल एक्टिविस्ट विवेक शर्मा ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें कहा कि जिले में दो राज्यमंत्रियों के होने के बावजूद छात्राओं की शिक्षा बाधित हो रही है। उनकी पोस्ट पर स्थानीय अभिभावकों ने कमेंट कर महाविद्यालय जल्द शुरू किए जाने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की मुहिम कागजों तक सिमट कर रह गई है। इसका लाभ छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है।

जल्द शुरू होगा कॉलेज

महाविद्यालय संचालन में शासन स्तर से कुछ समस्या आ रही थी। इसे दूर करने का प्रयास चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही महाविद्यालय में पठन–पाठन शुरू हो जाएगा।

लिस लिस्ट में जिला बदर वास्तव में साथियों के साथ मिलकर कर रहा था ताबड़तोड़ चोरी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में जिला बदर अपराधी ताबड़तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया तो यह खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस–प्रशासन की सक्रियता पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पकड़ा गया आरोपी शिव चौरसिया सितंबर में छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। यह अपने चार साथियों के साथ मिलकर शहर में चोरी कर रहा था। पारा पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने दो दुकानों में चोरी की बात कबूली है। दो दिन पहले चोरी कर ले गए सामान इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि मर्दन खेड़ा निवासी नरेश चंद्र मिश्रा की राजाजीपुरम के पीतांबर खेड़ा में मानसी इंटरप्राइजेज के नाम से और पीतांबर खेड़ा निवासी मुरारी लाल की राजपूत इंटरप्राइजेज के नाम से हार्डवेयर की दुकान से चोर नकदी व अन्य सामान दो दिन पहले चोरी कर ले गए थे। शनिवार रात पुलिस ने पांच आरोपियों हंसखेड़ा के सनी रावत, बीबी खेड़ा के सुमित यादव, सदरौना कॉलोनी के शिवा चौरसिया उर्फ जान, पीतांबर खेड़ा के करन सिंह उर्फ बउवा और उन्नाव के करवाल ताल बेहटा मुजावर निवासी विशाल रावत को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 20 हजार रुपये और कुछ सामान मिला है। इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हैं मुकदमे सनी के खिलाफ कृष्णानगर, सरोजनीनगर और पारा थाने में 12, सुमित यादव के खिलाफ अलीगंज व पारा थाने में आठ मुकदमे, शिवा के खिलाफ पारा थाने में 10 मुकदमे, विशाल रावत के खिलाफ तालकटोरा और पारा थाने में पांच और आरोपी करन सिंह के खिलाफ पारा थाने में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अब कजाकिस्तान में भी खुलेगा लविवि का कैंपस, शिक्षा के साथ बेहतर इंटर्नशिप का मिलेगा अवसर

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ स्थित लविवि प्रबंधन ने कजाकिस्तान में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। लखनऊ विश्वविद्यालय का यह संयुक्त परिसर ताजिकिस्तान में स्थित अलमाटी प्रबंधन विश्वविद्यालय के सहयोग से खोला जाएगा। यह जानकारी कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने दी। हालांकि अभी नेपाल में शैक्षणिक परिसर शुरू करने के दावे को 15 महीने बाद भी पंख नहीं लग सके हैं। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में 12 जनवरी को शिक्षकों का दल ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना हुआ था। वहां पर कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंध और गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एमओयू किए गए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेशी दौरे से लौटने के बाद इसकी जानकारी दी। कुलपति ने बताया कि कजाकिस्तान में प्रस्तावित लविवि के परिसर में एमबीए, बीबीए और अन्य विशेष पाठ्यक्रमों सहित प्रबंधन विज्ञान में कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे दोनों विवि के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ बेहत्तर इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। प्रो. आलोक ने कहा कि यह पहल साकार होती है तो इस शैक्षणिक साझेदारी से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती मिलेगी। कजाकिस्तान गोलमेज चर्चा की मेजबानी अलमाटी प्रबंधन विश्वविद्यालय के वाइस रेक्टर शोलपन तजावेक ने की। शिक्षा, पर्यटन–हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट में अंतरराष्ट्रीय, अंतर परिसर गतिशीलता व संबंधित उद्यमिता में विश्व स्तरीय व्यावसायिक वातावरण और बेहतर रणनीतिक योजनाओं को मजबूत करने के आयामों पर चर्चा हुई।

अक्टूबर 2023 में नेपाल गया था प्रतिनिधिमंडल

प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में अक्टूबर 2023 में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल नेपाल की शैक्षणिक यात्रा गया था। यहां से लौटने के बाद कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में लविवि का परिसर शुरू करने की बात कही थी। हालांकि, अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। यहां के चार विश्वविद्यालयों और तीन कॉलेजों का दौरा कर पांच एमओयू किए गए थे।

कुलपति ने मांगीं प्रो. बिमल के मामले से संबंधित पत्रावलियां

ताजिकिस्तान से लौटते ही कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने लविवि के शिक्षक प्रो. बिमल जायसवाल के मामले से संबंधित पत्रावलियां तलब की। उनकी नियुक्ति संबंधी मामले की जांच के लिए बनी समिति की पहली बैठक सोमवार को हो सकती है।

15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट

नियुक्ति में नॉन क्रीमी लेयर के मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। शासन ने इसकी जांच के लिए कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में समिति बनाई है। मामले की रिपोर्ट 15 दिन में मांगी गई है। हालांकि, 10 दिन बाद भी अब तक समिति की एक भी बैठक नहीं हो सकी है।

प्रदेश को मिलेंगी 15573 करोड़ रुपये की हाईवे परियोजनाएं, आगरा, मथुरा साहित इन जिलों को होने जा रहा लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में 15573 करोड़ रुपये की नई हाईवे परियोजनाएं जमीन पर उतरने जा रही हैं। इससे कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बरेली समेत कई जिलों की राह आसान होगी। इनमें से चार परियोजनाओं की वित्तीय बिड खुल चुकी हैं, जबकि पांच परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दिल्ली के सूत्रों के अनुसार, बरेली के 4–6 लेन दक्षिणी बाईपास के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। इसकी लंबाई 30 किमी होगी और अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपये है। इसी तरह से कबरई–कानपुर को फोरलेन करने और बाराबंकी–जरवल (पैकेज–1) मार्ग के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इनकी लागत क्रमशरू 3900 करोड़ और 1550 करोड़ रुपये है। बाराबंकी जरवल मार्ग का यह पैकेज–1 करीब 35.7 किमी लंबा होगा। बाराबंकी–जरवल मार्ग के पैकेज–2 में घाघरा नदी पर फोरलेन ब्रिज और आरओबी (रेलवे उपरिगामी सेतु) बनेगा। 7.3 किमी लंबी इस परियोजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जरवल से बहराइच के बीच 58.4 किमी सड़क निर्माण के लिए भी डीपीआर तैयार हो रही है। इसकी लागत 2050 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा कानपुर रिंग रोड फेज–2 और मथुरा–हाथरस–बदायूं–बरेली फोरलेन (पैकेज–4) के लिए वित्तीय बिड खुल चुकी हैं। एनएच–93 के आगरा–अलीगढ़ के 28 किमी लंबे पैकेज–1 और इसी हाईवे के 36.9 किमी लंबे पैकेज–2 के लिए भी वित्तीय बिड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन चार परियोजनाओं की बिड खुल चुकी हैं, उनकी कुल लागत 5324 करोड़ रुपये है।

संक्षिप्त समाचार

अयोध्या निर्मलीकुंड के आसपास घूम रहा तेंदुआ, न निकलें अकेले

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।वन विभाग ने कैंट क्षेत्र के जंगलों में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि के बाद सोमवार को अपील जारी की है। कहा है कि तेंदुआ निर्मलीकुंड के आसपास के जंगलों, नई फायरिंग रेंज और आसपास के जंगलों में घूम रहा है। इसलिए इन क्षेत्रों में अकेले न निकलें। जब भी बाहर जाएं, समूह में जाएं। मांझा क्षेत्र में आवागमन न करें। आसपास रहने वाले लोग घर में भी सतर्क रहें। प्रभागीय वनाधिकारी प्रखर गुप्ता ने बताया कि वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम लगातार गश्त कर रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़े लगा दिए गए हैं। इसे शीघ्र पकड़े जाने की उम्मीद है।

26 जनवरी से बिना हेलमेट के किसी भी पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।जिले में 26 जनवरी से पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। बाइक चालक के साथ पांच साल से ऊपर के सहयात्री को भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है। परिवहन आयुक्त का आदेश आने के बाद जिले के सभी 180 पेट्रोल पंप संचालकों को जिला आपूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिया है कि वह सात दिन के भीतर नो–हेलमेट नो फ्यूल का बोर्ड लगा लें।डीजल–पेट्रोल पंप परिसर में बड़े–बड़े होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करें कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा,जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेलमेट न पहना हो। यह भी सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। जिला आपूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में 180 के करीब पंप हैं। पेट्रोल के लिए चालक व पांच साल से ऊपर के सहयात्री को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

मौनी अमावस्या वसंत पंचमी पर राम लला के नहीं होंगे वीआईपी दर्शन

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।अयोध्या में मौनी अमावस्या व वसंत पंचमी पर्व पर महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद अयोध्या में उमड़ने वाली भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए रामलला के वीआइपी दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दर्शन अवधि भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व जिला प्रशासन की बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया की दर्शन लेन की संख्या भी बढ़ाई जायेगी।कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि महाकुंभ स्नान के बाद अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं का आंकलन किया जा रहा है। मौनी अमावस्या व वसंत पंचमी पर कितने श्रद्धालु आएंगे इसका भी अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि राम मंदिर में अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सके इसके लिए क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सुगम व विशिष्ट दर्शन के लिए दिए जाने वाले पास स्थगित किये जाएंगे। साथ ही श्रद्धालु ज्यादा सामान लेकर न आए, इसके लिए भी साइन बोर्ड लगाकर प्रचार प्रसार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि प्रशासन के साथ हुई बैठक में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इस पर जल्द विचार किया जाएगा।

कमरे में मिला प्रधान के बेटे का शव

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के इचवलिया ग्राम प्रधान हरि सिंह के इकलौते बेटे शिवम सिंह (21) का शव रविवार को संदिग्ध हालात में कमरे में बेड पर पड़ा मिला। गले पर कसे जाने का निशान था। उनके ससुर ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने आत्महत्या की बात बताई है। शिवम सिंह की शादी 5 दिसंबर 2023 को निगोहां के नंदौली निवासी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की बेटी दिव्या से हुई थी। दिव्या एमए की परीक्षा देने के लिए 13 जनवरी को मायके गई थीं। रविवार को शिवम का शव संदिग्ध हालात में कमरे में बेड पर पड़ा मिला। पिता हरी सिंह ने पुलिस को बताया कि कमरा अंदर से बंद कर बेटे ने पंखे से लटककर जान दे दी। दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा गया। खबर पाकर पत्नी व ससुराल वाले भी पहुंच गए। ससुर का कहना है कि शिवम के गले पर किसी चीज से कसे जाने के निशान थे। हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है।

संक्षिप्त समाचार

केतली, घंटी, कैमरा के साथ ही कमल और साइकिल निशान लेकर प्रत्याशी उतरे मैदान में

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।अयोध्याधमिल्कीपुर उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उप निर्वाचन 2025 के अन्तर्गत 273–मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के जारी कार्यक्रम के तहत आज नाम वापसी में किसी भी प्रत्याशी द्वारा नाम वापसी नही की गयी। जिसके क्रम में 273–मिल्कीपुर उपचुनाव 2025 के 10 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये है, जिसमें अजीत प्रसाद (समाजवादी पार्टी) साइकिल, चन्द्रभानु पासवान (भारतीय जनता पार्टी) कमल, राम नरेश चौधरी (मौलिक अधिकार पार्टी) आटो रिक्शा, सुनीता (राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोसलिष्ट) आरी, संतोष कुमार (आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)) केतली व निर्दलीय अरविन्द कुमार हाथ गाड़ी, कंचनलता द्वार घंटी, भोलानाथ अंगूठी, वेद प्रकाश फुटबाल खिलाड़ी, संजय पासी कैमरा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।

सावधान –Cyber Update : Jump Technic वाले इस नए स्कैम से बच के रहना

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।फोनपे, गूगल पे, पेटीएम या इसी तरह की अन्य यूपीआई का प्रयोग करने वाले लोगों को अब एक नए तरह के तरीके से ठगा जा रहा है, जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। इस तकनीक को Jump Technic का नाम दिया गया है। इसमें साइबर ठग आपको कोई छोटी राशि जिस पर आप शक ना करें भेजता है, जैसे कि 2000 यह राशि सच में ही आपको भेजी जाती है और आपके पास इसका जमा होने का टैक्स्ट मेसेज या नोटिफिकेशन भी आता है। इसमें ठग द्वारा तकनीक के जरिए ऑटोमैटिकली अमाउंट निकालने का सिस्टम सेट कर दिया जाता है। आप बैलेंस चेक करने के लिए जैसे ही यूपीआई पर जाकर अपना पिन डालते हैं, वैसे ही आपके खाते से अमाउंट उसे ट्रांसफर हो जाती है। इससे बचने का तरीका है कि जब भी आपके पास बिना उम्मीद के या किसी नदादवूद नंबर से पेमेंट आए तो आप यूपीआई पर चेक करने के लिए पहले एक बार जानबूझ कर गलत पिन डाल दें। ऐसा करने से ठग द्वारा सेट की हुई withdrawal अमाउंट अपने आप कैंसिल हो जाएगी।

इस पोस्ट को अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करें इससे पहले कि वो इस तरह के किसी ट्रैप का शिकार हो जाएं । Note:– ऐसे मामलों की रिपोर्ट 1930 या cybercrime.gov.in पर करें।

पूर्व प्रधान ने सरकारी जमीन पर बनवाया मकान

लखनऊ, (संवाददाता)। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाना पूर्व प्रधान को भारी पड़ गया। पूर्व प्रधान के बेशकीमती निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से गिराकर धराशाई कर दिया। पूर्व प्रधान ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया था। शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में प्रधान का घर गिराकर अवैध कब्जे को खाली कराया गया। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सकरावा गांव का है जहां गांव के ही पूर्व प्रधान हरिराम चौहान ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से घर बना लिया था। प्रशासन से शिकायत के बाद पहले उन्हें नोटिस दी गई लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने घर नहीं खाली किया तो आज प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। मौके पर पहुंचे एसडीएम न्यायिक और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रधान के घर पर कार्रवाई की गई है।

अपर मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन सॉन्ग का किया विमोचन

लखनऊ, (संवाददाता)। महाकुंभ क्षेत्र सेक्टर–7 में जल जीवन मिशन द्वारा स्थापित स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित के लिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग मंच प्रदान करेगा। रविवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने स्वच्छ सुजल गांव में स्थापित सांस्कृतिक समागम मंच का उद्घाटन किया। इस मंच के जरिए प्रदर्शनी देखने आने वाले तीर्थयात्रियों में अगर कोई अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे मंच पर मौका दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव द्वारा उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी में आई कई युवा प्रतिभाओं ने मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने स्वच्छ सुजल गांव की प्रदर्शनी के अलग–अलग स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द प्रदेश के 100 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में नल के जरिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने जल जीवन मिशन के नए सॉन्ग और जल धारा से जीवन धारा पुस्तिका का भी विमोचन किया। अपर मुख्य सचिव द्वारा विमोचन की गई पुस्तिका जल धारा से जीवन धारा में बताया गया है कि किस तरह से हर घर नल योजना ने लोगों का जीवन बदला है। इसमें ऐसी ही 11 कहानियों को बताया गया है। इस दौरान इंडियाज गॉट टायलेंट में परफॉर्म कर चुके मलखाम ग्रुप ने प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति को देख खचाखच भरा पंडाल तालियों से गूंछ उठा। मलखाम ग्रुप की प्रस्तुति में कलाकारों ने एक लकड़ी पर संतुलन के जो करतब दिखाए, उससे पंडाल में मौजूद 5,000 से अधिक लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने शिव तांडव पर प्रस्तुति दी। जिससे पंडाल के भीतर और पंडाल के बाहर खड़े श्रद्धालू भक्तिमय हो गए और वो भी शिव तांडव गाने लगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के बम बम भोले और ऊं नमरू शिवाय का जयकारा भी लगाया। करीब दो घंटों तक चले कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए अन्य कलाकारों के द्वारा भी प्रस्तुति दी गई।

साहित्यकार 24 राज्यकर्मियों को मिले एक-एक लाख के पुरस्कार

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश के रजत जयंती समारोह में रविवार को मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 24 राज्यकर्मियों को एक–एक लाख रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लखनऊ विवि के मालवीय सभागार में आयोजित समारोह में दो आईएएस समेत तीन शख्सियतों को साहित्य बंधु पुरस्कार, नौ साहित्यकारों को साहित्य गौरव पुरस्कार, वहीं तीन साहित्यकारों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य कर्मचारी प्रदेश के विकास में योगदान के साथ साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देकर दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि कुर्सी हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, हमें कुर्सी पर हावी होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने संस्थान की पत्रिका अपरिहार्य का विमोचन भी किया। पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों के पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। संस्थान की महामंत्री डॉ. सीमा गुप्ता ने संस्थान की यात्रा के बारे में बताया। आईपीएस आरके स्वर्णकार ने सभी रचनाकारों को बधाई दी। शिखा श्रीवास्तव, सरला शर्मा, श्रवण कुमार सेठ, पूर्व जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने काव्यपाठ किया। संचालन सुनील बाजपेई व अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष आईएएस अखिलेश मिश्र ने किया। शोभा दीक्षित 'भावना', चंद्रदेव दीक्षित, दिनेश अवस्थी, आदित्य तिवारी, रश्मिशील आदि का भी योगदान रहा। देवरिया के एसडीएम अवधेश निगम को एक लाख रुपये को महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, रिटायर्ड आईपीएस व पूर्व डीजी रहे जलगुरु महेंद्र मोदी को जोश मलिहाबादी पुरस्कार, गुजरात के डॉ. जशभाई एन. पटेल को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया। एक लाख के पुरस्कार पाने वालों में मोहम्मद अली साहिल को भगवती चरण वर्मा पुरस्कार, श्रीनिवास त्रिपाठी को सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार, आगरा के डॉ. सोम कुलश्रेष्ठ को भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, मुरादाबाद के अनुज अग्रवाल को अमृतलाल नागर पुरस्कार, प्रदीप कुमार पांडेय को डॉ. विद्या निवास मिश्र पुरस्कार, वाराणसी की प्रो. रचना शर्मा को श्याम सुंदर दास पुरस्कार, संतोष कुमार तिवारी 'कौशिल' को जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, कुलदीप किशोर तिवारी 'कलश' को शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार, ऋचा पाठक को हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार, गोरखपुर के सौदागर सिंह को रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार, आजमगढ़ के डॉ. शमीम इरशाद आजमी को गालिब पुरस्कार, डॉ. बिन्नो अब्बास रिजवी को फिराक गोरखपुरी सम्मान, रमाशंकर सिंह को अकबर इलाहाबादी पुरस्कार, अशोक पांडेय 'अनहद' को प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार, राम लखन यादव को शिव सिंह सरोज पुरस्कार, देवरिया के डॉ. सत्येंद्र कुमार सिंह को महादेवी वर्मा पुरस्कार, गाजीपुर की शमा परवीन को मीर तकी मीर पुरस्कार से नवाजा गया। संस्कृत संस्थान के पूर्व निदेशक दयाशंकर श्रीवास्तव, सुफलता त्रिपाठी, त्रिवेणी प्रसाद दुबे व प्रतापगढ़ के डॉ. जटाशंकर त्रिपाठी को भी एक–एक लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लखनऊ के पूर्व जिलाधिकारी और अब मुख्यमंत्री के सचिव सूर्यपाल गंगवार को साहित्य बंधु पुरस्कार दिया गया। आईएएस डॉ. वेदपति मिश्रा, लता कादंबरी को भी यही सम्मान मिला। इसके तहत प्रत्येक को 20 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई। कश्मीर की डॉ. अनिला सिंह चाड़क, डॉ. रामकृष्ण लाल जगमग, लोकेश त्रिपाठी, शालिनी पांडेय, संपत्ति कुमार मिश्रा, मुनेंद्र सिंह राठौर, सिराज मंजर काकोरवी, वंदना शुक्ला और प्रदीप सारंग को साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। इसके तहत सात हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई। रत्नदीप दीक्षित, अंशुल बंसल व विवेक सिंह को पांच हजार रुपये की सम्मान राशि के साथ प्रशंसा पत्र दिया गया।

फूलों की प्रदर्शनी में सीमैप इस साल भी अव्वल, 23 श्रेणियों में रहा प्रथम

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित दो दिवसीय वार्षिक गुलाब एवं ग्लैडिओलस प्रदर्शनी का रविवार का समापन हो गया। हर साल की तरह इस साल भी फूलों की प्रदर्शनी में सीमैप संस्थान अव्वल रहा। इस साल विभिन्न श्रेणी के 16 ट्रॉफियों में से कुल 11 ट्रॉफियां सीमैप की झोली में आए। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान (सीमैप) 205 में से 47 पुरस्कार जीतने के साथ ही 23 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार पाकर सर्वश्रेष्ठ रहा। सर्दी के मौसम में गुनगुनी धूप के बीच लगे इस दो दिवसीय प्रदर्शनी ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।